

बिहार में किसान आन्दोलन और स्वामी सहजानंद सरस्वती

डॉ. रंजीत कुमार

+2 Teacher, Ashok Inter School Daudnagar Aurangabad Bihar-824143

बिहार में किसान आंदोलन की एक समृद्ध परंपरा रही है। चंपारण का सन् 1917 का किसान आंदोलन इसी की एक कड़ी था। चंपारण में उन दिनों तिनकठिया प्रथा थी। इस प्रथा से स्थानीय किसान असंतुष्ट थे क्योंकि खाद्यान्न के संकट के साथ-साथ भूमि की उर्वरा शक्ति का भी इस प्रथा के कारण नाश हो रहा था। गांधीजी ने अब तक चंपारण का नाम न सुना था।¹ वहां नील की खेती होती है, इसका भी ख्याल नहीं के बराबर था। इस बात की जानकारी गांधी जी को पहले पहल राजकुमार शुक्ल से प्राप्त हुई थी। राजकुमार शुक्ल चंपारण के एक किसान थे। उन्होंने लखनऊ की सभा में गांधीजी से मुलाकात की और उनके वकील बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद ने किसानों के दुख का हाल बताया।² चंपारण के बारे में कांग्रेस की महासभा में ब्रजकिशोर बाबू बोले और सहानुभूति- प्रकाशक प्रस्ताव पास हुआ। लखनऊ से गांधी जी कानपुर गये। वहां भी राजकुमार शुक्ल मौजूद थे। कलकते में गांधीजी के भूपेन बाबू के पहुंचने के पहले ही शुक्ल ने वहां डेरा डाल रखा था। गांधीजी को 'इस अपढ़, अनगढ़ पर निश्चयवान किसान ने जीत लिया था'³ बिहार में उस समय वकिलों का एक मंडल था जिसमें ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद तथा रामनवमी प्रसाद आदि प्रमुख थे। ये सभी गरीब किसानों के लिए लड़ते थे।

राष्ट्रीय स्तर पर सामंत विरोधी संघर्षों एवं किसान आंदोलन की एक नई लहर सन् 1920 ई0 में शुरू हुई।⁴ संयुक्त प्रांत का अवध क्षेत्र किसान सभा आंदोलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार था।⁵ वहां के तालुकदारों के असहनीय शोषण और उत्पीड़न के चलते किसान बाबा रामचन्द्र के नेतृत्व में जुझारू संघर्ष छेड़ चुके थे जो कई बार हिंसात्मक रूप धारण कर लेता था।⁶ कांग्रेस चूंकि अब तक मध्यमवर्ग के लोगों की ही संस्था बनाकर काम कर रही थी इसलिए इन किसान आंदोलनों का इसके साथ कोई अंतरगता कायम न हो सकी थी। ये किसान आंदोलन कांग्रेस से बिलकुल अलग थे। देशव्यापी जो असहयोग आंदोलन आरंभ हो रहा था उसका इससे कोई ताल्लुक न था।⁷ यहीं क्यों, खुद कांग्रेस की भी शुरू के दिनों में बराबर यहीं मांग थी कि जहां-जहां अभी बंदोवस्त नहीं हो पाया है, वहां स्थायी बंदोवस्त कर दिया जाय कि जिससे जमींदारों के अधिकारों की रक्षा हो सके, और उसमें किसानों का कहीं जिक्र तक नहीं रहता था।⁸ इसी राष्ट्रीय प्रादेशिक परिदृश्य के बीच स्वामी

सहजानंद सरस्वती ने सन् 1920 ई0 में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। स्वामी जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक गांधीवादी के रूप में की थी। उन्होंने गांधीजी के प्रत्येक आदेश का पालन अक्षरशः करने की कोशिश में चरखा और तकली चलाना भी शुरू कर दिया था।⁹ कांग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से उन्होंने कांग्रेस के सभी वार्षिक अधिवेशनों में भाग लिया।¹⁰ किसान क्रांति को साम्राज्यवाद के विरुद्ध चल रहे संघर्ष का एक अभिन्न अंग मानते हुए स्वामीजी की धारणा थी कि शोषित बहुमत के सहयोग के बिना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सफलता संदिग्ध है। किसान समस्याओं के प्रति अपनी सतत् जागरूकता, निष्ठा एवं कटिबद्धता के कारण स्वामी जी ने 1928 में पटना तथा 1929 में सोनपुर मेले में जिला स्तरीय किसान सभाओं का आयोजन किया एवं बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की।¹¹ कहना अनावश्यक है कि 1929 में किसान सभा की शुरुआत गांधीवादी समझौते के सिद्धांत की नीति के तहत की थी।¹²

किंतु सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान स्वामी जी की जेल-यात्रा और वहां के अनुभव तथा 1934 के भूकंप से उत्पन्न परिस्थितियों में किसानों पर जमींदारों द्वारा किये गए अत्याचार ने स्वामीजी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि गांधीवादी रास्ते से जमींदारों-पूँजिपतियों के हृदय की कल्पना करना भी सत्य से दूर भागना है।¹³

1933 के अप्रैल एवं 1935 के नवंबर के बीच की अवधि में बिहार के दस जिलों में लगभग पांच सौ किसान सभाएं आयोजित की गयी। 1937 के हाजीपुर में प्रांतीय किसान सम्मेलन के साथ-साथ इन जिलों में सैंकड़ों छोटी-बड़ी किसान सभाएं भी आयोजित हुईं। यद्यपि किसान सभा उस वक्त मुख्यतः धनी और मध्यम किसानों के उपरी हिस्सों का ही प्रतिनिधित्व करती थी।¹⁴ फिर भी आम किसान भी इस सभा की ओर आकर्षित होने लगे थे क्योंकि किसानों का हित जिससे सधे इस पर वह कुछ भी करने को तैयार थे।¹⁵ किसानों के संगठन में वैज्ञानिक विचारों के प्रवेश और समावेश तथा राष्ट्रीय आंदोलन के साथ नाता जुड़ने से किसान आंदोलन में एक उभार आने लगा।

किसान सभा के उद्देश्यों में बिना मुआवजा के जमींदारी उन्मूलन के प्रस्ताव का स्वामी जी ने 1934 ई0 में विरोध किया था पर 1935 के सम्मेलन में उन्होंने स्वयं इस प्रस्ताव को पेश किया। 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन ने

किसानों की कई मांगों को अपने कार्यक्रम में शामिल कर लिया। उसी साल फैजपुर के कांग्रेस अधिवेशन ने इसी आधार पर अपना कृषि-सुधार प्रस्ताव तैयार किया।¹⁶ 1937 में नेहरू ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि फैजपुर कृषि कार्यक्रम का 'महान महत्व' है। 1937 में नेहरू का यह भी मानना था कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या किसान समस्या है, बाकि सब गौण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 'हमें अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति ईमानदारी रहना है और किसानों की आशाओं को संतुष्टि और पूर्णता प्रदान करनी है।'¹⁷ फैजपुर का यही कृषि सुधार प्रस्ताव आनेवाले चुनाव के लिए घोषण-पत्र का आधार बना और कांग्रेस की जीत करा दी। कुछ ही महीनों के बाद छपरा जिले के मसरख में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन ने किसान सभा के जमींदारी उन्मूलन वाले प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया।¹⁸ उत्साह में कांग्रेस के अंदर जितने कांग्रेस सोशलिस्ट या अन्य थे, सबों ने मिलकर एक बैठक में स्वामी जी राहुल जी और किशोरी प्रसन्न सिंह को लेकर एक उपसमिति बनायी। उपसमिति का काम इसी प्रस्ताव के आधार पर कांग्रेस प्रतिनिधियों का चुनाव करना था। ख्याल यह था कि प्रतिनिधियों के चुनाव में बहुमत प्रतिनिधि इसी विचार के हो जाये तो प्रांतीय कांग्रेस कमिटी मंत्रिमंडल को जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का आदेश देती।¹⁹ किंतु एक बार सत्ता में पहुंचने के बाद यह नेतृत्व सामान्यतः वाम को और विशेषतः किसान सभा को नियंत्रित करने के साधनों और रास्तों की तलाश करने लगा।

बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के सदस्य और बिहार किसान सभा के अध्यक्ष सहजानंद को चंपारण, सारण, और मुंगेर जिले की कांग्रेस कमिटियों ने निर्देश दिया कि वे उनके

जिलों की यात्रा न करें। दिल्ली की कांग्रेस महासमिति की बैठक में आलाकमान की ओर से एक प्रस्ताव आया कि प्रांतीय कांग्रेस कमिटी की अनुमति के बिना कोई कांग्रेसजन किसान संघर्षों में नहीं पड़ सकता। गांधीजी के हस्तक्षेप पर उस समय प्रस्ताव को आलाकमान ने वापस कर लिया। पर कुछ ही दिनों बाद यही प्रस्ताव बंबई कार्यसमिति द्वारा स्वीकृत करा दिया गया। यही नहीं प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि कोई कांग्रेसजन इस प्रस्ताव के खिलाफ कहीं बोल नहीं सकता।²⁰ स्थानीय कांग्रेसियों को धमकी दी गई कि यदि वे उसकी बैठकों में गए तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।²¹ गौरतलब है कि यह प्रतिबंध उस समय लगाया गया जब दक्षिणपंथी कांग्रेसियों ने जमींदारों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उन दोनों ने किसान आंदोलन को कुचलने के लिए आपस में गठजोड़ कर लिया था।

जमींदारों के एजेंटों और दक्षिणपंथियों के अनुयायियों ने जिलों से सहजानंद की यात्रा को असफल करने की अपनी ओर से भरसक कोशिश की किंतु किसानों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर उनकी कोशिशों को विफल कर दिया। सहजानंद बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्य थे किंतु दक्षिणपंथियों के समर्थन से निचले स्तर की कांग्रेस समितियों ने उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की। प्रदेश कांग्रेस समिति ने बाद में इस कर्तव्य का समर्थन किया। किसान सभा को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया। सहजानंद सरस्वती ने नागरिक स्वतंत्रता का मामला उठाया।²² किंतु प्रसाद और पटेल सभी स्तरों पर किसान सभा का विरोध करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। अंततः स्वामी जी और किशोरी प्रसन्न सिंह तीन साल के लिए कांग्रेस से बाहर किए गये।²³

संदर्भ

1. मोहनदास करमचंद गांधी, आत्मकथा, सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1984, पृष्ठ 374
2. वही
3. वही, पृष्ठ 375
4. सी.पी. आई.(एम.एल) के लिए अरिंदम सेन तथा पार्थ घोष द्वारा संपादित भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन, खंड-01(1917-39), समकालीन प्रकाशन, पटना अक्टूबर 1992, पृष्ठ 50-51
5. वही
6. जवाहर लाल नेहरू, मेरी कहानी, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, 1988 पृष्ठ-94-95
7. जवाहर लाल नेहरू, पूर्वोद्धृत
8. वही
9. स्वामी सहजानंद सरस्वती, मेरा जीवन संघर्ष, पृष्ठ 118
10. दशरथ तिवारी, कृषि और 'कृषि समन्वय' स्वामी सहजानंद सरस्वती: ओंकार से हुंकार तक (मुख्य संपादक: विजयचंद्र प्रसाद चौधरी), राहुल प्रेस पटना 1990, पृष्ठ 84
11. उपेन्द्र नारायण सिंह, किसानों के प्राण स्वामी सहजानंद सरस्वती: ओंकार से हुंकार तक पृष्ठ 88
12. रेणु शर्मा, 'वर्ण से वर्ग की ओर' स्वामी सहजानंद सरस्वती: ओंकार से हुंकार तक पृष्ठ 98
13. वही
14. किशोरी प्रसन्न सिंह, 'राह की खोज में' अन्वेषा प्रकाशन पटना 2003 पृष्ठ 163
15. वही
16. वही
17. कपिल कुमार, 'किसान कांग्रेस और स्वतंत्रता संग्राम: 1917-39' सांचा (हिन्दी पत्रिका) अक्टूबर 1988
18. किशोरी प्रसन्न सिंह, पूर्वोद्धृत, पृष्ठ 163
19. वही
20. किशोरी प्रसन्न सिंह पूर्वोद्धृत पृष्ठ 166
21. वही
22. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, 05 जून 1938
23. किशोरी प्रसन्न सिंह, पूर्वोद्धृत, पृष्ठ 167